

नवा भारत



4 क्या 30 दिनों में जमानत मिलना संभव?

5 बाढ़ से हालात खराब राहत कार्यों में तेजी

8 आईसीसी ने महिला विश्व कप के पुरस्कार राशि में चार गुना की वृद्धि

9 भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

एक नजर में



सिंगापुर के प्रधानमंत्री आज भारत आयेंगे

भूकंप से 800 लोगों की मौत

अफगानिस्तान में भारी तबाही, 2800 से अधिक घायल

6.0 तीव्रता का भूकंप रविवार रात 11.47 बजे आया

2023 में आए भूकंप से 4 हजार की हुई मौत

नयी दिल्ली, 1 सितम्बर. अफगानिस्तान में रविवार देर रात और सोमवार की सुबह आए शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई है. पाकिस्तान सीमा के निकट नंगरहार और कुनार प्रांत में आए इस भूकंप से सोमवार शाम तक 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2800 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, रविवार रात को

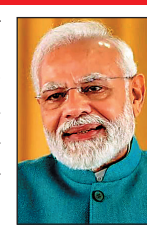


स्थानीय समयानुसार 11.47 बजे अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में 6.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसका केंद्र जलालाबाद

शहर से 27 किलोमीटर दूर और आठ किलोमीटर की गहराई में था. इसके बाद सोमवार सुबह 4.5 से 5.2 तीव्रता के तीन और झटके

मोदी ने जानमाल के नुकसान पर जताया शोक

मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान में आये भूकंप में हुई जान-माल की हानि से अत्यंत दुःखी हूँ. इस कठिन घड़ी में हमारी संवेदनाएँ और प्रार्थनाएँ शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं. भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तत्पर है.

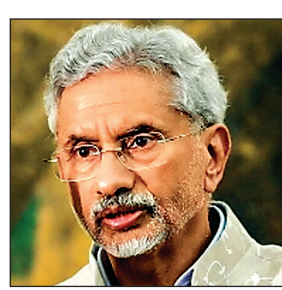


महसूस किए गए. झटके काबुल और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक महसूस किए गए. तालिबान सरकार के अनुसार, सबसे ज्यादा तबाही कुनार के पहाड़ी इलाकों में हुई है. कई गांव पूरी तरह ढह गए हैं और राहत कार्य में मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि भूस्खलन के कारण कई सड़कें बंद हो चुकी हैं. तालिबान ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हेलीकॉप्टर और अतिरिक्त मदद की अपील की है. स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता

शराफत जमान ने बताया कि प्रभावित इलाकों में चिकित्सा दल भेजे गए हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण बचाव अभियान धीमा है. अधिकारियों का कहना है कि मृतकों और घायलों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कई इलाके अब भी दुर्गम हैं. गौरतलब है कि अफगानिस्तान भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है. अक्टूबर 2023 में भी यहां आए 6.3 तीव्रता के भूकंप में करीब 4,000 लोगों की मौत हुई थी.

भारत ने अफगानिस्तान में एक हजार तंबू और 15 टन खाद्य सामग्री भेजी

नई दिल्ली, 1 सितम्बर. भारत ने अफगानिस्तान में भूकंप से हुई भारी तबाही के बाद मदद का हाथ बढ़ाते हुए तत्काल सहायता के तौर पर वहां एक हजार तंबू व 15 टन खाद्य सामग्री भेजी है. विदेश मंत्री डा. एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी से बात कर भूकंप के कारण हुई जान-माल की हानि पर संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस कठिन समय में भारत अफगानिस्तान के साथ है. उन्होंने कहा कि भारत ने 1000 परिवारों के लिए काबुल में एक हजार तंबू पहुंचाए हैं. काबुल स्थित भारतीय मिशन द्वारा कुनार तक 15 टन खाद्य सामग्री भी तुरंत पहुंचाई जा रही है. उन्होंने कहा कि



भारत की ओर से कल और राहत सामग्री भेजी जाएगी. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ. इस कठिन समय में भारत अफगानिस्तान के साथ है. उल्लेखनीय है पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार और नंगरहार प्रांतों में रविवार रात आये भूकंप कम से कम 800 से अधिक लोगों की मौत हो गयी.

टीईटी के बिना पढ़ा सकेंगे शिक्षक पांच साल से कम समय वाले शिक्षकों को पात्रता : सुको

नयी दिल्ली, 1 सितम्बर. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की योग्यता और अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि जिन शिक्षकों को सेवा में पांच साल से कम समय बचा है, वे शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास किए बिना पढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा. वहीं जिनकी नौकरी में पांच साल से ज्यादा सेवा शेष है, उन्हें दो साल के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. न्यायालय ने टिप्पणी की कि कई शिक्षक पिछले बीस वर्षों से बिना टीईटी योग्यता के पढ़ा रहे हैं और उन पर किसी प्रकार



की शिकायत नहीं है. कोर्ट ने 2014 के प्रमाटी फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह जांच आवश्यक है कि बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर किस हद तक लागू होता है. इस अब मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है, ताकि सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ इस पर विचार कर सके.

स्टालिन ने जर्मनी में किये 3201 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर

चेन्नई, 01 सितंबर (वार्ता). तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने यूरोपीय देशों के अपने पहले चरण में सोमवार को तीन जर्मन कंपनियों के साथ 3201 करोड़ रुपये के निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये. इन दिनों वह राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिये विदेश यात्रा पर हैं. इसके अलावा स्टालिन ने प्रमुख कार निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू की एक उच्च स्तरीय टीम के साथ परिचालन विस्तार बाटचीत की. स्टालिन कोलोन में अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद जर्मनी की अपनी यात्रा के दूसरे दिन डुसेलडोर्फ पहुंचे.

अभी एटम बम अगला होगा 'हाइड्रोजन बम'

वोट चोरी के खुलासे पर बोले राहुल गांधी

पटना, 01 सितम्बर. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को पटना में वोट अधिकार यात्रा के समापन समारोह में कहा कि अब तक हुआ वोट चोरी का खुलासा 'एटम बम' था, आगे आने वाला खुलासा 'हाइड्रोजन बम' होगा, जिसके बाद चुनाव आयोग और भाजपा को मुंह छिपाना मुश्किल होगा. राहुल ने आरोप लगाया कि



महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करोड़ों फर्जी वोट भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से जोड़े गए थे. बेंगलुरु सेंट्रल की एक सीट पर एक लाख फर्जी वोट मिलने और बिहार में मतदाता

समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा 2014 से ही सात हथियाने के लिए वोट चोरी, धनबल और एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है. भाजपा-माले महासिव दौकर भद्राचार ने नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन को भाजपा की साजिश बताते हुए कहा कि एसआईआर ने वोट चोरी को उजागर कर दिया है.

खत्म करना चाहती हैं. इसी बीच बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को याद दिलाते हुए कहा कि यह बिहार की धरती है, लोकतंत्र की जननी है.

भारत ने अमेरिका पर लगाया ज्यादा टैरिफ : ट्रंप

वाशिंगटन, 01 सितंबर (वार्ता). अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क घटा कर 'नगण्य' करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो चुकी है. ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत ने लंबे समय से अमेरिकी उत्पादों पर दुनिया में सबसे अधिक कर लगाता आ रहा है और इस कारण दोनों देशों के बीच व्यापार एकतरफा है. उन्होंने इसे एकतरफा विनाश बताया.



भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाकर 01 अगस्त से 25 प्रतिशत कर दिया था जिसे 27 अगस्त को दो गुना कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है. अमेरिका के इस कदम के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गयी है. ट्रंप ने कहा कि काफी कम लोग यह समझते हैं कि अमेरिका भारत से काफी कम

व्यापार करता है, जबकि भारत अमेरिका से काफी व्यापार करता है. उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ग्राहक है और भारत उसे बड़ी मात्रा में सामान बेचता है जबकि वह अमेरिका से बहुत कम खरीदता है. उन्होंने भारत में अमेरिकी उत्पादों पर ऊंचे आयात शुल्क को इसका कारण बताया है, यह पूरी तरह से एकतरफा विनाश था. अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर रूस से तेल खरीदने के लिए भारत की आलोचना की. उन्होंने कहा, भारत ज्यादातर कच्चा तेल और सैन्य उत्पाद रूस से खरीदता है, हमसे उसकी खरीदारी बहुत कम है.

मोदी-पुतिन-जिनपिंग की मुलाकात से हिला अमेरिका

ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों और अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर भारी आयात शुल्क को लेकर दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न तनाव की बीच अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को कहा दोनों देशों की साझेदारी लगातार नयी ऊंचाइयों को छू रही है. दूतावास ने विदेश मंत्री माको रुबियो के इस आशय के एक बयान वाले पोस्टर के साथ सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में कहा कि भारत-अमेरिका संबंध 21 वें सदी की एक निर्णायक भागीदारी है.

आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी यूसीसी

नयी दिल्ली, 1 सितम्बर. केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) आदिवासी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी. उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों को उनकी पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार जीने की आजादी दी जाएगी और उनके अधिकारों की पूरी सुरक्षा की जाएगी. आरएसएस से जुड़े वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में रिजिजू ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर कुछ लोग केंद्र सरकार के खिलाफ गलत नैरेटिव षड रहे हैं, जबकि सच्चाई



यह है कि आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि जब देश में फौजदारी कानून सभी के लिए समान हैं तो नागरिक कानून अलग-अलग क्यों हों. इसी सोच के तहत सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने

पर विचार कर रही है. रिजिजू ने बताया कि उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर दी है और वर्तमान में विधि आयोग इस पर विचार कर रहा है. हालांकि अनुसूची-5 और अनुसूची-6 के तहत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर राज्यों को इससे छूट दी जाएगी. भगवान बिरसा मुंडा भवन में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन अवसर पर रिजिजू ने कांग्रेस पर भी परोक्ष हमला बोला. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय दिल्ली में आदिवासियों के लिए कोई बड़ा संस्थान नहीं था और मंत्रिपरिषद में भी उनका समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होता था.

25वां शिखर सम्मेलन आतंकवाद मानवता का शत्रु है और इस पर किसी तरह का दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं

एससीओ के मंच से मोदी का राष्ट्र प्रथम संदेश



तियानजिन/नयी दिल्ली, 01 सितम्बर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 25वें शिखर सम्मेलन में संगठन की दिशा तय करते हुए साफ कहा कि आतंकवाद मानवता का शत्रु है और इस पर किसी तरह का दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं होगा. एससीओ के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक स्तर पर बड़ी जीत हासिल करते हुए राष्ट्र प्रथम का संदेश दिया. उन्होंने 10 बार आतंकवाद का जिक्र करते हुए इस मंच से स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद पर

दोहरा रवैया किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा. क्योंकि विश्व की शांति के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है. एससीओ समिट में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी एक कार में ही निकले और तकरीबन 60 मिनट तक एक दूसरे के बीच बातचीत हुई. इस दृश्य को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में जबरदस्त बौखलाहट देखी जा रही है. इस बीच ट्रंप का यह बयान आया कि भारत ने हम पर ज्यादा टैरिफ लगाया है और वह रूस से तेल खरीदता है, इस बात को पुष्ट करता है कि इस महामिलन से अमेरिका की सुपरपावर की छवि

डगमपाने लगी है. मोदी ने चेताया कि सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले ढाँचों पर अंकुश लगाए बिना क्षेत्रीय शांति और स्थिरता संभव नहीं है. उन्होंने हाल के पहलगाम आतंकी हमलों का जिक्र कर कहा कि ऐसे कृत्य किसी एक देश के विरुद्ध नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अंतरात्मा पर हमला हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ वार्ता में सुरक्षा, कनेक्टिविटी और सहयोग को तीन प्रमुख स्तंभ बताया. उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी की परियोजनाएँ सभी सार्थक होंगी जब संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होगा.

समित के प्रमुख बिंदु

- आतंकवाद को बताया साझा खतरा
- सीमा-पार ढाँचों पर रोक की मांग
- संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता पर जोर
- रूस-यूक्रेन युद्ध पर शांति का संदेश
- कनेक्टिविटी में स्थानीय हितों का ध्यान
- पुतिन से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा
- ऊर्जा व व्यापार सहयोग पर सहमति
- लोकतांत्रिक मूल्यों पर भारत की प्रतिबद्धता